



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 742]  
No. 742]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 30 2008/ज्येष्ठ 9, 1930  
NEW DELHI, FRIDAY, MAY 30, 2008/JYAISTHA 9, 1930

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मई, 2008

आय-कर

का.आ. 1273(अ).—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80-इसख की उपधारा (9) के तीसरे परंतुक के खंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित उपक्रमों को, जो खनिज तेल परिष्करण परियोजनाएं हैं, उक्त उपधारा के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

- (i) पारादीप, उड़ीसा स्थित इंडियन आयल कार्पोरेशन लि० की 15 एमएमटीपीए क्षमता परिष्करण परियोजना ;
- (ii) बीना, मध्य प्रदेश स्थित भारत ओमान रिफाइनरी लि० की 6 एमएमटीपीए क्षमता परिष्करण परियोजना ;
- (iii) भटिण्डा, पंजाब स्थित एचपीसीएल-मित्तल एनर्जी लि० की 9 एमएमटीपीए क्षमता (लगभग 12 एमएमटीपीए थ्रुपुट सहित) परिष्करण परियोजना ;
- (iv) सीपीएफ, गंधार, अंकलेश्वर, गुजरात स्थित तेल और प्राकृतिक गैस निगम लि० की 3000 बीओपीडी (387 टीपीडी) क्षमता लघु- परिष्करण परियोजना ;
- (v) मंगलौर, कर्नाटक स्थित मंगलौर रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स लि० की 5.31 एमएमटीपीए क्षमता फेज-3 परिष्करण परियोजना ;
- (vi) विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश स्थित हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० की 7.5 एमएमटीपीए क्षमता नई विसाख परिष्करण विस्तारण परियोजना ;
- (vii) तातिपाका, राजामुन्दरी, आंध्र प्रदेश स्थित तेल और प्राकृतिक गैस निगम लि० की 1500 बीओपीडी (193 टीपीडी) क्षमता यूनिट 2 लघु - परिष्करण परियोजना ; और
- (viii) पानीपत, हरियाणा स्थित इंडियन आयल कारपोरेशन की 3 एमएमटीपीए क्षमता पानीपत परिष्करण विस्तारण परियोजना ।

2. उपरोक्त की अधिसूचना निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी कि—

- (i) खनिज तेल परिष्करण परियोजनाएं आय-कर अधिनियम की धारा 80-इख के अर्थ के भीतर पृथक उपक्रम का गठन करती हैं ;
- (ii) उपक्रम 31 मार्च, 2012 के अपश्चात् खनिज तेल के परिष्करण का कार्य आरंभ करता है ; और
- (iii) उपक्रम पूर्णतया किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी या किसी ऐसी अन्य कंपनी के स्वामित्वाधीन बनी रहती है, जिसमें पब्लिक सेक्टर कंपनी या कंपनियां कम से कम उन्चास प्रतिशत मताधिकार रखती हैं ।

[अधिसूचना सं. 66/2008/फा. सं. 142/5/2005-टीपीएल]

शोभन कर, अवर सचिव

**MINISTRY OF FINANCE**  
(Department of Revenue)  
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)  
**NOTIFICATION**  
New Delhi, the 30th May, 2008  
**Income-Tax**

S.O. 1273(E).—In exercise of the powers conferred by clause (ii) of the third proviso to sub-section (9) of section 80-IB of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies the following undertakings, being mineral oil refinery projects, for the purposes of the said sub-section, namely:-

- (i) 15 MMTPA capacity refinery project of Indian Oil Corporation Ltd. at Paradip, Orissa;
- (ii) 6 MMTPA capacity refinery project of Bharat Oman Refineries Ltd. at Bina, Madhya Pradesh;
- (iii) 9 MMTPA capacity (with thruput around 12 MMTPA) refinery project of HPCL – Mittal Energy Ltd. at Bathinda, Punjab;
- (iv) 3000 BOPD (387 TPD) capacity mini-refinery project of Oil & Natural Gas Corporation Ltd. at CPF, Gandhar, Ankleshwar, Gujarat;
- (v) 5.31 MMTPA capacity Phase-III refinery project of Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd at Mangalore, Karnataka;
- (vi) 7.5 MMTPA capacity New Visakh refinery expansion project of Hindustan Petroleum Corporation Ltd. at Vishakapatnam, Andhra Pradesh;
- (vii) 1500 BOPD (193 TPD) capacity unit II of mini-refinery project of Oil & Natural Gas Corporation Ltd., at Tatipaka, Rajahmundry, Andhra Pradesh; and
- (viii) 3 MMTPA capacity Panipat refinery expansion project of Indian Oil Corporation at Panipat, Haryana.

2. The notification of the above shall be subject to conditions that -

- (i) the mineral oil refinery projects constitute a separate undertaking within the meaning of section 80-IB of the Income-tax Act;
- (ii) the undertaking begins refining of mineral oil not later than the 31<sup>st</sup> day of March, 2012; and
- (iii) the undertaking continues to be wholly owned by a public sector company or any other company in which a public sector company or companies hold at least forty-nine per cent of the voting rights.

[Notification No. 466/2008/F. No. 142/5/2008-TPL]

SOBHAN KAR, Under Secy.